

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम *The Tribune*
दिनांक *16.4.2019* पृष्ठ सं. *4* कॉलम *1-2*

HAU, Netherlands to work on crop residue management

DEEPENDER DESWAL
TRIBUNE NEWS SERVICE

HISAR, APRIL 15

Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University (HAU) and the Netherlands have joined hands to work on a project to tackle problems faced in management of paddy straw in the state.

A four-member delegation led by Siebe Schuur, counsellor for agriculture, nature and food quality, from the embassy of the Netherlands in India, came to the university and called on Prof K P Singh, Vice-Chancellor of HAU. Siebe assured the university of support in its efforts for the management of crop residue, particularly paddy straw. He said the Dutch companies were eager to invest in India and also appreciated the efforts of the university in sorting

out the issue of paddy straw in the state.

The paddy straw management is a serious problem in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. Due to lack of appropriate technology and methods, farmers are forced to burn the paddy straw which creates the problem of environmental pollution. However, the HAU is seriously working for providing simple and economical options to the farmers for safeguarding the environment as well as the management of paddy straw. The university has also got a project worth Rs 4 crore from the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to develop suitable technologies for crop residue management and popularise the available methods and machinery among the farmers.

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम *The Hindustan Times*
दिनांक *16.4.2019* पृष्ठ सं.*2*..... कॉलम*8*.....

Netherlands to tie up with Hisar varsity for paddy straw mgmt

HT Correspondent

■ letterscd@hindustantimes.com

HISAR : The Netherlands will cooperate with Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University (CCSHAU) in its efforts for management of paddy straw in Haryana, a four-member delegation led by Siebe Schuur, counsellor for agriculture, nature and food quality from the embassy of the Netherlands in India, said on Monday. The delegation met university vice-chancellor KP Singh and said companies in Netherlands are eager to invest in India in the project related to paddy straw management. Paddy burning is a critical issue in states such as Haryana, Punjab and Uttar Pradesh where every year, the air quality index gets affected due to stubble burning.

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम समग्र उजाला
दिनांक 16.4.2019 पृष्ठ सं. 6 कॉलम 4-8

पराली प्रबंध

नीदरलैंड्स के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किया एचएयू का दौरा, कुलपति प्रो. केपी सिंह से की मुलाकात, संयुक्त समूह का गठन किया

धान की पराली के प्रबंधन में एचएयू का सहयोग करेगा नीदरलैंड्स

अमर उजाला व्यूरो

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड्स सहयोग करेगा। नीदरलैंड्स के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के कार्टेसलर सीधे शूटर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आया।

प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. केपी सिंह से मुलाकात की। रखे ने विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयास में पूरा सहयोग देने का अवसरमन दिया। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। सीधे के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी कार्टेसलर



एचएयू के वीसी प्रो. केपी सिंह से मुलाकात करत धान की पराली के प्रबंधन विषय को लेकर दौर पर आया नीदरलैंड्स का प्रतिनिधिमंडल।

आनंद कुम्हण और दो इंटरन डेनिकल व मान शामिल रहे।
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली की गंभीर समस्या : धान की खेती करने वाले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधियों उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं,

जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। पर्यावरण को सुरक्षा और किसानों को धान की पराली प्रबंधन के लिए सरल और किफायती विकल्प देने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने और इस कार्य के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने और मशीनों व यंत्रों को किसानों में

लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से चार करोड़ रुपये की परियोजना भी मिली है। वहां यह भी बता दें कि धान की पराली के सही समाधान की दिशा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और भारत में नीदरलैंड्स दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ संयुक्त समूह का गठन किया गया है, जिसने इस माह के शुरू में नीदरलैंड्स

दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की। तीन दिन चली इस बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉ. आरके झोराड़, एडि्टर विषय विशेषज्ञ डॉ. रवि गुला, डॉ. मुकेश जैन, डॉ. वादिका और डॉ. कमल मलिक शामिल हुए थे। इनके अतिरिक्त भारत के कई सैद्धांतिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सेट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्री उद्योग ने भी इस बैठक में भाग लिया। नीदरलैंड्स के प्रतिनिधिमंडल ने हफ्ते के ऑफिसरों, कैजल्टी और विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत की और संयुक्त रूप से किए जाने वाले सैद्धांतिक और अनुसंधान कार्यों का पता लगाया। इस प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं और संरचनाओं का दौरा किया और वहां जारी गतिविधियों में रुचि दिखाई।

समाचार-पत्र का नाम हरिभूमि

दिनांक 16.4.2019 पृष्ठ सं. 12 कॉलम 2-6

हकृवि में पहुंचा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

पराली प्रबंधन में हकृवि की मदद करेगा नीदरलैंड, निवेश को तैयार

■ कहा, नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक

हरिभूमि न्यूज ॥ हिसार



हिसार। हकृवि कुलपति प्रो. केपी सिंह के साथ बैठक में उपस्थित नीदरलैंड्स प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

फोटो : हरिभूमि

हकृवि द्वारा धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड सहयोग करेगा। नीदरलैंड के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के कार्टेसलर सीबे शूडर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हकृवि आया।

इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. केपी सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर सीबे ने इस विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयास में

पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी कार्टेसलर आनंद कुण्णन और दो इंटरन डैनियल व मारन शामिल थे। हकृवि को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से

चार करोड़ रूपए की एक परियोजना भी मिली है। धान की पराली के स्थायी समाधान की दिशा में हकृवि और भारत में नीदरलैंड्स दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं।

संयुक्त समूह का किया गठन

पराली प्रबंधन के हितधारकों के साथ एक संयुक्त समूह का गठन किया गया है। जिसने इस माह के

शुरू में नीदरलैंड्स दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की।

बैठक में यह हुए शामिल

तीन दिन चली इस बैठक में हकृवि से अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉ. आरके झोरड़, डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. मुकेश जैन, डॉ. यादविका और डॉ. कमला मलिक शामिल हुए थे। इनके अतिरिक्त भारत के कई

हरियाणा-पंजाब में समस्या

धान की खेती करने वाले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधियां उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है।

शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्री उद्योग ने भी बैठक में भाग लिया।

इस अवसर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम सैनिक जागरण

दिनांक 16-4-2019 पृष्ठ सं.18..... कॉलम 1-4.....

योजना

देश में पराली प्रबंधन की परियोजनाओं में निवेश करेंगी नीदरलैंड की कंपनियां

नीदरलैंड दूतावास के अधिकारी पहुंचे एचएयू

जागरण संवाददाता, हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड सहयोग करेगा। नीदरलैंड के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के काउंसलर श्रीसीबे शूजर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. केपी सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर श्रीसीबे ने इस विश्वविद्यालय की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। श्रीसीबे के नेतृत्व में यहां आए प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के



कुलपति प्रो. केपी सिंह के साथ बैठक में उपस्थित नीदरलैंड्स प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

डिप्टी काउंसलर आनंद कृष्णन, डैनियल और मारन शामिल थे।

पाराली पर एचएयू और नीदरलैंड दूतावास एक साथ कर रहे काम
: धान की पराली के स्थायी समाधान की दिशा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और भारत में नीदरलैंड दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ एक संयुक्त

समूह का गठन किया गया है, जिसने इस माह के शुरू में नीदरलैंड दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की। तीन दिन चली इस बैठक में एचएयू से अनुसंधान निदेशक डा. एसके सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डा. आरके झोरड़ सहित विषय विशेषज्ञ डा. रवि गुप्ता, डा. मुकेश जैन, डा. यादविका और डा. कमला मलिक शामिल हुए थे।

मिली 4 करोड़ की परियोजना

धान की खेती करने वाले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधियां उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा होती है।

इनके अतिरिक्त भारत के कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्रो उद्योग ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम

दिनांक 16.4.2019 पृष्ठ सं. 3 कॉलम 1-3

एचएयू के साथ पराली प्रबंधन पर काम के लिए नीदरलैंड की कंपनियां निवेश को तैयार तीन दिन तक नीदरलैंड के पदाधिकारियों के साथ एचएयू में चली हाईलेवल बैठक

भास्कर न्यूज़ | हिसार

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की पराली के प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड्स सहयोग करेगा। नीदरलैंड्स के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के कार्डेसलर सीबे शूटर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. केपी सिंह से मुलाकात की।

इस अवसर पर सीबे ने इस एचएयू द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने हरियाणा में धान की पराली की समस्या को हल करने के लिए कुलपति की पहल, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी कार्डेसलर आनंद कृष्णन और दो इंटरनैशनल व मारन शामिल रहे। तीन दिन चली बैठक में एचएयू से अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉ. आरके झोरड़ सहित विषय विशेषज्ञ डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. मुकेश जैन, डॉ. यादविका और डॉ. कमला मलिक शामिल हुए।



पराली प्रबंधन पर नीदरलैंड के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. केपी सिंह।

इन संस्थानों ने हिस्सा लिया

इनके अतिरिक्त भारत के कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड इंजीनियरिंग, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्री उद्योग ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अनेक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया।

पराली प्रबंधन क्यों जरूरी

धान की खेती करने वाले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य में पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधियां उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों को धान की पराली प्रबंधन के लिए सरल और किफायती विकल्प देने के लिए एचएयू प्रयास कर रही है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम पंजाब केसरी
दिनांक 16.4.2019 पृष्ठ सं. 3 कॉलम 3-5

एच.ए.यू. द्वारा धान की पराली के प्रबंधन के लिए अब नीदरलैंड करेगा सहयोग



कुलपति प्रो. के. पी. सिंह के साथ बैठक में उपस्थित नीदरलैंड प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

हिसार, 15 अप्रैल (ब्यूरो): नीदरलैंड के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के काउंसलर सीबे शूटर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. के. पी. सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर सीबे ने इस विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन हेतु किए जा रहे

प्रयास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।

सीबे के नेतृत्व में यहां आए इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी काउंसलर आनंद कृष्णन और 2 इंटरन डैनियल व मारन शामिल थे। धान की पराली के स्थायी समाधान की दिशा में हरियाणा

कृषि विश्वविद्यालय और भारत में नीदरलैंड्स दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ एक संयुक्त समूह का गठन किया गया है जिसने इस माह के शुरू में नीदरलैंड्स दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की। 3 दिन चली इस बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुसंधान निदेशक डॉ. एस. के. सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉ. आर. के. झोरड़ सहित विषय विशेषज्ञ डा. रवि गुप्ता, डा. मुकेश जैन, डा. यादविका और डा. कमला मलिक शामिल हुए थे। इनके अतिरिक्त भारत के कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्रो उद्योग ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया।

समाचार-पत्र का नाम नम चौधरी
दिनांक 16.4.2019 पृष्ठ सं. 3 कॉलम 6-8

धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में हकृवि को सहयोग देगा नीदरलैंड्स



हिसार/15 अप्रैल/रिपोर्टर

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड्स सहयोग करेगा। नीदरलैंड्स के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के काउंसलर सीबे शूटर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय आया। इस अवसर पर सीबे ने इस विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने हरियाणा में धान की पराली की समस्या को हल करने के लिए कुलपति प्रो. केपी सिंह की पहल, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। सीबे के नेतृत्व में यहां आए इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी काउंसलर आनंद कृष्णन और दो इंटरन डैनियल व मारन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि धान की

खेती करने वाले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधियां उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों को धान की पराली प्रबंधन के लिए सरल और किफायती विकल्प देने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. केपी सिंह के मार्गदर्शन में गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने और इस कार्य के लिए फलहाल उपलब्ध विधियों और मशीनों व यंत्रों को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से चार करोड़ रूपए की एक परियोजना भी मिली है। यहाँ यह भी बता दें कि धान की पराली के स्थायी समाधान की दिशा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और भारत में नीदरलैंड्स दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए

विभिन्न हितधारकों के साथ एक संयुक्त समूह का गठन किया गया है जिसने इस माह के शुरू में नीदरलैंड्स दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की। तीन दिन चली इस बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉ. आरके शोरड सहित विषय विशेषज्ञ डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. मुकेश जैन, डॉ. यादविका और डॉ. कमला मलिक शामिल हुए थे। इनके अतिरिक्त भारत के कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्रो उद्योग ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया। इस मौके पर नीदरलैंड्स के प्रतिनिधिमंडल ने हकृवि के अधिकारियों, फैकल्टी और विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत की और संयुक्त रूप से किए जाने वाले शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यों का पता लगाया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम

नित्य शक्ति 21/4/2019

दिनांक 15-4-2019. पृष्ठ सं.6..... कॉलम 1-3.....

पराली प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड करेगा हकूवि का सहयोग

हिसार, 15 अप्रैल (निस)। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड्स सहयोग करेगा। नीदरलैंड्स के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के काउंसलर श्री सीबे शूटर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. के. पी. सिंह से मुलाकात की।

इस अवसर पर श्री सीबे ने इस विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने हरियाणा में धान की पराली की समस्या को हल करने के लिए कुलपति प्रो. केपी सिंह की पहल, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

श्री सीबे के नेतृत्व में यहां आए इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी काउंसलर आनंद कृष्णन और दो इंटरन डैनियल व सुश्री मारन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि धान की खेती करने वाले



हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधियां उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों को धान की पराली प्रबंधन के लिए सरल और किफायती विकल्प देने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. केपी सिंह के मार्गदर्शन में गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने और इस कार्य के लिए फिलहाल उपलब्ध विधियों और मशीनों व यंत्रों को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से चार करोड़ रूपए की एक परियोजना भी मिली है।

यहां यह भी बता दें कि धान की पराली के स्थायी समाधान की दिशा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और भारत में नीदरलैंड्स दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न

हितधारकों के साथ एक संयुक्त समूह का गठन किया गया है जिसने इस माह के शुरू में नीदरलैंड्स दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की। तीन दिन चली इस बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुसंधान निदेशक डॉ. एस.के. सहरावत, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डीन डॉ. आर.के. झोरड़ सहित विषय विशेषज्ञ डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. मुकेश जैन, डॉ. यादविका और डॉ. कमला मलिक शामिल हुए थे। इनके अतिरिक्त भारत के कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्रो उद्योग ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया। इस मौके पर नीदरलैंड्स के प्रतिनिधिमंडल ने हकूवि के अधिकारियों, फैकल्टी और विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत की और संयुक्त रूप से किए जाने वाले शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों का पता लगाया। इस प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं और सरचनाओं का दौरा किया और यहां जारी गतिविधियों में रुचि दिखाई।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम हिसार
दिनांक 15-4-2019 पृष्ठ सं. 4 कॉलम 7-8

हकृवि के पराली प्रबंधन पर नीदरलैंड्स सहयोग करेगा

हिसार : 15
अप्रैल चौधरी
चरण सिंह
हरियाणा कृषि
विश्वविद्यालय



द्वारा धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड्स सहयोग करेगा। नीदरलैंड्स के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के काउंसलर श्री सीबे शूडर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. के. पी. सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री सीबे ने इस विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयास में पूरा

सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने हरियाणा में धान की पराली की समस्या को हल करने के लिए कुलपति प्रो. के. पी. सिंह की पहल, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। श्री सीबे के नेतृत्व में यहां आए इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी काउंसलर श्री आनंद कृष्णन और दो इंटरन श्री डैनियल व सुश्री मारन शामिल थे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम सिटी पत्र
दिनांक 15.11.2019 पृष्ठ सं. 2 कॉलम ... 1-4

पराली प्रबंधन की दिशा में नीदरलैंड करेगा हरियाणा कृषि विवि का सहयोग

सिटी पत्र न्यूज़, हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की पराली के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्य में नीदरलैंड्स सहयोग करेगा। नीदरलैंड्स के भारत में दूतावास से कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के काउंसिलर सीबे शूटर के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. केपी सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री सीबे ने इस विश्वविद्यालय द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विशेषकर धान की पराली के प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयास में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नीदरलैंड्स की कंपनियां धान की पराली प्रबंधन से संबंधित परियोजना में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने हरियाणा में धान की पराली की समस्या को हल करने के लिए कुलपति प्रो. केपी सिंह की पहल, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

सीबे के नेतृत्व में यहां आए इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता के डिप्टी काउंसिलर आर्नंद कृष्णन और दो इंटरनल य सुश्री मान शर्मिल थे।

उल्लेखनीय है कि धान की खेती करने वाले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली के प्रबंधन की गंभीर समस्या है। उचित प्रौद्योगिकी या विधि उपलब्ध न होने के चलते किसान धान की पराली को



हिसार। कुलपति प्रो. केपी सिंह के साथ बैठक में उपस्थित नीदरलैंड्स प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

जलने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों को धान की पराली प्रबंधन के लिए सरल और किफायती विकल्प देने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. केपी सिंह के मार्गदर्शन में गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने और इस कार्य के लिए फिलहाल उपलब्ध विधियों और मशीनों व यंत्रों को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से चार करोड़ रुपये की एक परियोजना भी मिली है। उन्होंने बताया कि धान की पराली

के स्थायी समाधान की दिशा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और भारत में नीदरलैंड्स दूतावास एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ एक संयुक्त समूह का गठन किया गया है जिसने इस ग्राह के शुरू में नीदरलैंड्स दूतावास में इस विषय को लेकर बैठक भी की। तीन दिन चले इस बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहाय, कृषि इंजीनियरिंग कालेज के डॉन डॉ. आरके झोरड़ सहित विषय विशेषज्ञ डॉ. रवि गुप्त, डॉ. मुकेश जैन, डॉ. नादिका और डॉ. कमला मलिक शामिल हुए थे। इनके अतिरिक्त भारत के कई शोधनिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ

फैक्ट्रिंग, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पेपर उद्योग, भारतीय एग्री उद्योग ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक अंतराष्ट्रीय कंपनियों एवं अनुसंधान समूहों ने अपनी प्रौद्योगिकियों की स्थापना किया।

इस मौके पर नीदरलैंड्स के प्रतिनिधिमंडल ने इकृति के अधिकारियों, फैक्टरी और विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत की और संयुक्त रूप से किए जाने वाले शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों का पता लगाया। इस प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं और संरचनाओं का दौरा किया और यहां जारी गतिविधियों में रुचि दिखाई।